बड़े-बड़े शहरों के पास ही लगाई जाती हैं। ये अफसर लोग तय करते हैं कि यह फेक्ट्री शहर के पास ही लगाई जानी चाहिए। आप हमारे बड़ौदा शहर को ले लीजिए। इस 10 लाख की आबादी वाले शहर की हालत है कि यहां पर इतनी केमिकल फेक्ट्रीज लग गई हैं कि उनके धुएं से रात को बिलकुल चादर सी चढ़ जाती है। आप थोड़ी दूर तक देख भी नहीं सकते हैं। ओ०एन०जी०सी० के जो सिलेन्डर्स हैं उनसे भी गैस निकलती है। तीन चार दिन पहले मैं सुबह बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा कि चारों तरफ धुआ ही धुआ है। आजकल हालत यह है कि पैट्रोल महंगा है, इसलिए लोग उसमें मिट्टी का तेल मिला देते हैं जिसके कारण सड़कों पर चलने वाले वीहकल्स भी धूआ छोड़ते हैं। अहमदाबाद में थर्मल पावर स्टेशन भी धुआ छोड़ता है। इस वजह से सारे शहर में धुआ छा जाता है। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि हमारी सरकार को 25 किलोमीटर की दूरी पर जहां पर कोई आबादी न हो वहां पर इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए ताकि अगर गैस का लीकेज भी तो कम से कम नुकसान हो। अभी शहरों में जो फेक्ट्रीज लगी हुई हैं उनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जाना चाहिए और अगर उनको शिफ्ट नहीं किया जाता है तो उन पर कड़ा से कड़ा नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। इन फेक्ट्रीज को लगाने के लए जहां पर उनके मालिकों को जिम्मेवार समझते हैं वहां अफसरों को भी इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वे ही लोग इनकी क्लीयरेन्स देते हैं।

REEKENCE TO THE NEED TO PRO-TBCT DIRDS FROM FROM RADIOVITY HAZARD

श्री रशीद मसूद (उत्तर प्रदेश) : चेयरमैन साहब, सर्दी की आमद के साथ हमारे मुल्क में परिन्दे आते हैं। ये परिन्दे हर साल आते हैं और साइबेरिया से आते हैं। लेकिन हर साल और इस साल इन परिन्दों के आने में थोड़ा सा फर्क हुआ है जिसकी वजह से मुझे यह मामला इस सदन में उठाना पड़ रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (मध्य प्रदेश) : आप भी बहुत दिनों बाद आये हैं।

श्री रशीद मसूद : मैं आपके साथ ही निकला था और आपके साथ ही आया हूं।

पिछले दिनों चेरनोबिल का जो वाक्य हुआ है, एटामिक रिऐक्टर के बर्स्ट होने का उस पर अभी इजराइल और स्पैन के साइंटिस्ट्स ने रिसर्च की और उन्होंने पाया है कि पानी के अंदर जहां परिन्दे आकर ठहरते हैं उनमें रेडियो ऐक्टिव मैटीरियल पाया गया। हमारे यहां पर क्योंकि इजराइल और स्पैन से मुखतलिफ बात यह भी है कि तमाम पाबन्दियों के बावजूद बहुत बड़ी तादाद में उस का शिकार किया जाता है और उनको खाते भी है। इस कारण उनके साथ जो रेडियो एक्टिव मटीरियल आता है वह हमारे मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिये बहुत जल्दी से जल्दी हम कोई न कोई उपाय करना चाहिए और खासतौर पर जो बर्ड सैंक्चूरी हैं उनमें एटामिक इनर्जी कमीशन की टीम जायं और वे जाकर वहां रिसर्च करें और देखें कि कितना रेडियो ऐक्टिव मैटीरियल परिन्दों के साथ आया है। ऐसा तो नहीं है कि उसकी तादाद ज्यादा है और उससे हमारे यहां के रहने वाले लोगों या जो टूरिस्ट लोग वर्ड वाचिंग के लिए आते हैं उनको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा ? दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की तो यह राय है कि अगले दस साल इसके कारण तकरीबन 10 लाख आदमियों को कैंसर होने की उम्मीद है। इससे पहले कि कोई ऐसी बात हो जाय और बात हमारे हाथ से बाहर चली जाय मैं आपके जरिए सरकार से यह दरखवास्त करना चाहूंगा कि सरकार इस

[**उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल)** : पीठासीन हुए।]

मामले में, खासतौर पर जहां बहुत बड़ी तादाद में परिन्दे आते हैं, उन बर्ड सैंक्चूरी

[श्री रशीद मसूद]

में हमारे स्टामिक इनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट्स की टीम जाय और वह वहां रिसर्च करके देखे कि जो रेडियो एक्टिव मैटीरियल उन परिन्दों के साथ आया है वह कितनी तादाद में आया है ? क्या वे पिछले सालों की तादाद के मुकाबले में यहां पहुंचे हैं, कितनी तादाद में परिन्दे मारे गये हैं ताकि हमें यह अंदाजा हो सके कि इसका क्या असर हुआ है और देश के लोगों को रेडियो ऐक्टिव मैटीरियल से नुकसान न हो ।

REFERENCE TO THE REPORTED SPREAD OF ENCEPHALITIS IN THE COUNT

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बीमारी इनसाइफिलिटिस की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह 1978 में इस देश में बड़े प्रकोप के साथ आई थी और इसकी भयानकता इतनी अधिक थी कि डाक्टर भी जो मरीज को देखने जाता था वह भी इससे एफेक्टेड हो जाता था और वह भी मर जाता था । इससे डाक्टर भी परेशान थे । उस समय से आज तक लगातार यह बीमारी कुछ न कुछ रूप में सम्पूर्ण देश में धीरे-धीरे व्याप्त हो रही है और आज तक हम इसके लिए कोई अनुकूल दवा, टीका और इंजक्शन का निर्माण नहीं कर सके हैं । जापान के इसके लिए एक दवाई निकाली है, इंजक्शन निकाला है लेकिन उस दवाई को लेकर इतने बड़े देश की आबादी के लिहाज से इस रोग को रोकना संभव नहीं है । इसके अलावा भी जिस तापमान में इस दवा को रखना चाहिए उसको रखना भी हर जगह संभव नहीं है । इसलिए यह रोग इस देश में एक महामारी का रूप धारण करता जा रहा है । इसलिए इसको रोकने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग, को अनुसंधान संस्थाओं को कड़े कदम उठाने चाहिए । उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय वैज्ञानिक इस बीमारी की दवा के क्षेत्र में कोई कारगर कदम नहीं उठा पाई है । इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार निश्चित रूप से इस बीमारी से निजात पाने के लिए कोई न कोई खास व्यवस्था करे अन्यथा यह बीमारी एक महामारी का रूप ले लेगी हैजा चला प्लेग चला लेकिन अब यह बीमारी एक महामारी का रूप लेकर मौत का कारण बन सकती है । इसलिए सरकार इस ओर अपना ध्यान दे ।

REFERENCE TO THE SCARCITY OF POTABLE WATER IN GUJARAT

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, due to successive failures of the monsoon in Saurashtra and other parts of Gujarat, the problem of drining water has assumed the form of acute crisis. During last year, the potable water crisis was so acute that water had to be transported in trains running over the distance of 200 kms. This time because of second successive failure of the rains in Saurashtra, ground water resources tapped last year mostly, are no longer mobilisable, either the underground waters have gone further deep or turned saltish or have dried up. Gujarat Government is preparing a mastar plan to make potable water available to the people but the technical and the financial resuorces of the State have been overstrained during last year's scarcity and it is going to be extremely difficult for the State Government, this year to further shoulder the burden of the water crisis spread over the larger parts of Gujarat compared to last year's scarcity conditions.

The delayed clearance of Rs. 6000 crores Narmada Irriagtion Project of national importance has to an extent added to the problem of water-crisis. The Ministry for Environment and Forests has held up the clearance of the Project for the proposal of diversion of about 13,000 hectares of forest land of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra for the Sardar Srovar Project in Broach district of Gujarat is since long under the consideration of the Central Government and it is also